MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that amendment No. 5 moved by Shri Bapusaheb Parulekar be withdrawn.

Amendment No. 5 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : Shri Giridhar Gomango has another amendment No. 6. He is not here. I shall now put amendment No. 6 moved by Shri Giridhar Gomango to the vote of the House.

Amendment No. 6 was, put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Resolution moved by Shri Giridhar Gomango to the vote of the House.

The question is :

> "This House urges upon the Government to take immediate steps to implement the policies and programmes adopted in Sub-plan for trial areas and the Component plan for Scheduled Castes of the country for socio-economic upliftment of the people and also to ask the States and Union Territories to execute the same vigorously so that the growing unrest and discontentment among the Adivsis due to the exploitation by the vested interests and the atrocities committed on Harijans is cheked and their interests are protected in the larger interests of the nation as a whole."

The motion was negatived

16.15 hrs.

RESOLUTION *RE.* STEPS TO INCREASE FOOD PRODUCTION

MR. CHAIRMAN : We now go to the next item.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, आप पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए।

नं० 2 और नं० 3 पर जो रेजोल्यूशन हैं वे दोनों समान हैं। अगर कोई इस तरह का नियम है, जसा कि प्रश्नों में करते है कि दोनों को एक साथ लिया जा सके तो हम चाहेंगे कि दोनों प्रस्तावों को एक साथ पेश किया जाए और उसी के हिसाब से समय का एडजस्टमेंट कर लिया जाए।

MR. CHAIRMAN As you are aware, there is no such procedure. But you may be accommodated a little more.

Prof. Satya Deo Singh.

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं:

> "देश की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग कृषि पर निर्भर है और उसकी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह उर्वरकों, बीजों और कृषि उपकरणों के मूल्यों को कम कर के, सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर के किसानों को आधुनिकतम खेती के तरीकों से अवगत कराके, उनको उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कर के तथा फसल और पशु बीमा योजनाएं आरम्भ कर के उन्हें उचित प्रोत्साहन दे ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके।"

सभापति महोदय, यह बात सही है कि स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश में औद्योगिक विकास करने के लिए सफल प्रयास किए और कल-कारखानों की उन्होंने भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, हटिया (रांची) में स्थापना की। साथ-ही साथ उनका ध्यान इस बात की ओर भी गया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, जैसे गंडक योजना, कोसी योजना और भाखड़ा-नांगल, फरक्का बांध आदि की स्थापना कर के उन्होंने किसानों को राहत देने का प्रयास किया और इसके लिए आज हमारी प्रधान मं

जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी प्रयास कर रही हैं। भूमिहीन किसानों को मकान देने के लिए, बन्धवा मजदूरी का खात्मा करने के लिए तथा देहातों में जहां पर खेत-मजदूर रहते हैं, जिनको साल भर का काम नहीं मिलता है, इसके साथ-साथ अतिवृष्टि और अनावृष्टि तथा बाढ़ के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है और किसानों का जीवन भी संकटग्रस्त हो जाता है, इन सब चीजों की ओर सरकार ने ध्यान दिया है। वैसे हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाओं की संभावनाओं को लेकर सरकार ने, हमारी प्रधान मंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्होंने किसानों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने का प्रयास किया है। ये सभी किसानों के लिए बड़े ही हितकारी कार्यक्रम है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इस विशाल देश में अभी भी किसानों की दशा सुधर नहीं सकी है। अभी उनके जीवन में दुर्दिन है। अनावृष्टि और अतिवृष्टि तथा भयंकर बाढ़ के चलते उनकी फसल नष्ट हो जाती है, इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह परमावश्यक हो जाता है कि सरकार खेती के जितने उपकरण हैं, खाद है बीज है – इन सभी सामग्रियों को सस्ते दर पर किसानों को मुहैया करे, फसल और बीमा योजना लागू करे जिससे किसानों को आर्थिक दशा सुधर सके। फसल नष्ट हो जाने की वजह से उनकी कमर टूट जाती है और दूसरों से कर्ज लेकर उनको अपना काम करना पड़ता है और कभी-कभी तो भुखमरी की हालत भी पैदा हो जाती है उन किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन किसानों को बचाने के लिए कोई भी देखने वाला नहीं होता और वे अपने आपको भाग्यहीन समझने लगते हैं और भयंकर निराशा के जीवन में आ जाते हैं।

एक तरफ देश की आजादी मिलने के बाद जहां पर कल-कारखानों और उद्योग में काम करने वालों को साल भर रोजी रोटी मिलती है, फसल नष्ट होने से किसान निराश हो जाता है। इस लिए किसानों के जीवन में उत्साहवर्धन करने के लिए यह परमावश्यक है कि सरकार उन्हें कृषि उत्पादों का समार्थित मूल्य देकर प्रोत्साहन दे, चाहे वह खेत में काम आने वाली वस्तुओं और उपकरणों के दाम कम करके या किसी भी रूप में हो, लेकिन सरकार को उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं। फसल और पशु बीमा योजना लागू करनी चाहिए। हमारे देश में सिंचाई की संतोषप्रद व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है और बिजली पर्याप्त मात्रा में समय पर न मिलने के कारण, खास कर हमारे बिहार प्रदेश में खेती मारी जाती है, जिसकी वजह से खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों और खेत मजदूरों की तो हालत और भी खराब हो जाती है।

इसलिए आवश्यक है कि सरकार सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करायें। हमारे कृषि मजदूर जो फसलों के मारे जाने से बेकार हो जाते हैं, उनके जीवन को समुन्नत और सबल बनाने की दृष्टि से, उन के जीवन को अन्य वर्गों के समान बनाने की दृष्टि से, ताकि उन्हें भी इस आजादी का कुछ लाभ मिल सके, सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिएं। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार के अब तक के प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों और खेतिहर-मजदूरों को जितनी राहत मिलनी चाहिए, अभी

[प्रो० सत्य देव सिंह]

तक नहीं मिल सकी है। हमारी प्रधान मंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, लेकिन फिर भी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक काम करने की जरूरत है——इसी लिए मैंने इस प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"In view of the fact that about three fourth of the population of the country is dependent on agriculture and has a vital role in the economy of the country, this House recommends to the Government to give proper incentives to the farmers by reducing the prices of fertilizers, seeds and farm implements, providing irrigation facilities acquainting them with latest farming techniques, ensuring remunerative prices of their produce and introducing crop and cattle insurance schemes so that food production may increase."

SHRI R. K. MHALGI (Thane): I beg to move:

That in the resolution,—

(i) *after* "farm implements" *insert*—"and other inputs".

(ii) *after* "irrigation" *insert*—"and credit"

(iii) *after* "prices of their produce" *insert*—"covering full cost of production and considering living index."(1)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I beg to move:

That in the resolution—

add at the end——

"and further recommends that 100 per cent income-tax exemption be given on income from any investment made in mango, cashew and other food crops for a period of 10 years." (3)

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Chairman, Sir, the present resolution really highlights the problems which the farmers are facing in our country. The subject of land reforms has been one of the most important and urgent ones before the country so far as the rural area is concerned. Many of the important economists and even many of the foreign writers who visited this country suggested that there should be strong political will to implement the land reform measures in this country. It is a good thing that in the years, 1971 to 1976, the land reform measures were implemented very seriously and with a strong political determination. Out of the total declared surplus land of 15.74 lakh hectares in 1978, only about 9.56 lakh hectares have been taken possession of by the States as on March, 1980 and, out of that, only about 6.79 lakh hectares of land have been distributed so far. Therefore, I hope that within the coming two years, the Government would distribute the entired 15.74 lakh hectares of land declared surplus. We got this surplus land as a result of land ceiling. But, I find that the implementation of this measure of land reforms is very tardy and slow. It should be implemented within a time-bound programme of two years so that the difficulties of the landless agriculturists can be overcome to some extent. The farmers should be benefited from these land reforms. Most of these lands are being distributed to the landless, to the weaker sections of society, and to the poor people and to the Harijans. In the Sixth Plan draft it is said that the land distribution programme itself seems to be vary tardy and not much effort seems to have been made to assist the allottees to develop the land. In my State of Orissa, we have distributed more than 1 lakh acres of land to the landless. But, in many cases, the pattas have not been given. The lands have not been identified. Naturally, they cannot take possession of the lands. Because of the financial difficulties of the farmers, they are not able to raise crops in the land. Therefore, I am very happy that the Sixth Plan itself has discusssed these problems and they have suggested that more financial assistance should be given to those landless people who have been given in the land. It is one of the 20-point programme that house-sites should be given to those who have no homes. It is a very good thing, and since 1971, 7.7 million house-sites have been allotted to the landless is the rural areas of our country.

In this connections I would also suggest that the Land Reforms Acts which have been passed in many of the States have not yet been included in the Ninth Schedule of the Constitution. I hope, immediate measures will be taken to see that those Acts, which have not yet been included, are included in the Ninth Schedule, so that protection to such measures is afforded.

All of us are very happy that, in order to given protection to more than 8 crores of landless agricultural workers, our Government have decided, in consultation with all the leading rural workers' organisations, to have an Agricultural Workers' Bill. In all the meetings of the Agricultural Workers' Committees, this was discussed and we have decided; the Government has also agreed. The draft Bill is already there. We were told that the Bill would be introduced in the last Session itself, in November-December last year. But it has not yet been introduced. Now we have a long time in this Session. At least in this Session, the Bill should be introduced and it should become an Act, so that it gives protection to 8 crores of agricultural workers in the countryside.

The credit system in the countryside must be highlighted. The farmers need more and more credit, so that they can increase production. But what we do find there? We have opened so many branches of commercial banks; there are village banks and cooperative credit institutions. But what is happening? There are considerable regional imbalances in giving credits. You will find that the rural credit is more in areas like Andhra Pradesh and Maharashtra than in areas like Bihar or Orissa or North-Eastern State. You find regional imbalances even in pumping out credit to the farmers. These imbalances should be removed.

In regard to institutional credit to agriculture and allied activities, in the Sixth Plan, I am very happy, they have projected to expand the base from a total of Rs. 2,550 crores in 1979-80 to Rs. 5,415 crores by 84-85. They want to expend the base. It is a good thing. But to day the commercial baks take more deposits from the rural side, to the extent of 10·6 per cent; and what they give as credit advances to the rural areas is only 8·2 per cent. They take more from the rural people, they take their savings and deposits, and pump them out to the cities and to industrial centres. The rural people are starved of credit; they got only 8·2 per cent. This should be looked into.

There is great difficulty in so-far as the question of overdues is concerned so far as commercial bank credit is concerned, the overdues are 50 per cent; in cooperative credit, the overdues are 42 per cent. You will find that, all over the country, these credits to the farmers range from 10 to 20 years; and interest is added on to it. Now the farmers the medium and the small farmers, have made a claim. Upto a certain point of time, the interest should be excluded, so that the credit does not go on mounting up; sometimes it goes up to a very high figure. Till a certain point of time-we have to fix the time-the interest at least should not be charged from our farmers who are trying hard to see that production increases.

Another question which comes up is building up of reserve. Unless we try to build up a reserve of 10 to 15 million tonnes of foodgrains; it would be difficult. Yesterday it has been pointed out in the Economic Survey that the reserve has come down from 11·1 million tonnes to 10 million tonnes. we have to fix the reserve at 15 million tonnes, so that in the event of drought or other natural calamities, our economy is strengthened and we will be able to say that nothing will happen so far as price escalation is concerned in difficult times. This should be looked into.

Another point is social security to farmers. I think, the national employment guarantee Scheme should be introduced in every Block.

That way at least we will see that more and more people get employment and it creates more and more productivity.

With regard to stability in prices, this will not be possible unless the farmers get a remunerative price for their produce. We are happy that recently the prices of sugar cane, cotton, wheat and rice have been increased. But simultaneously the prices of the inputs also have increased. So, I would suggest that farmers, the consumers and all others concerned should sit together and work out a remunerative price to the farmer. The industrial goods fetch a higher price whereas when the farm produce goes to the market, it is priced much less. Therefore, the farmer is in a difficult position This disparity should be removed and some sort of a balance struck in this matter.

I support the resolution of my hon. friend, Prof. Satya Deo Sinha. Sir, the time has come when we should see that more fertiliazerss, more inputs and more irrigation facilities are made available to the farmer. To-day only 25 to 27 per cent of our land is under irrigation and 75% is rain-fed. Now, in the Sixth Plan agriculture is given top priority and a massive allocation has been made for agriculture. As it is the farmer who sustains the country, we must try to see that we help the farmers in all possible ways. They are the backbone of this country. It is our duty to see that he survives and prospers so that he can help the country.

SHRI BAPUSAHAB PARULEKAR (Ratnagiri) : Sir, I rise to support this

[Shri Bapusahab Parulekar]

resolution moved by Prof. Satya Deo Sinha.

At the outset I congratulate him for having focussed the attention of this august House to this important resolution with reference to the steps to increase food production. By this resolution the mover is recommending to the government that proper incentives to farmers be given for increasing food production and the incentives suggested by him are that price of fertilisers be reduced, prices of seeds and implements be reduced, irrigation facilities be provided, the farmer should be acquainted with the latest farming techniques, renmunerative prices should be ensured and a cattle insurance scheme be introduced.

Sir, it is very difficult within the time allotted to me to refer to all these points. So, in my submissions I would try to restrict myself mainly to the quetstion of fertilisers and prices and acquainting the farmers with the latest farming techniques....

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : Also minimum wages for agricultural workers.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : I am referring to the Resolution. Therefore, I restrict myself to the resolution. There are many things. When I said that it is not possible for me within the time available to refer to all these things, how can I go to other things ?

Coming to the question of fertilisers, it is not only the question of supplying fertilisers at reduced rates but I find that the government is not in a position to supply the necessary quantity of fertilisers to the farmers. The annual consumption of fertilisers, according to government statistics, are on the increase. I believe it is a good indicator of the country's performance in crop production. But it is necessary that certain steps will have to be taken to see that the necessary quantities of these fertilisers are made available to the farmers if we want to have sufficient food production.

Sir, the statistics how that in 1974-75 the indigenous production was 15·1 lakh tonnes and in 1979-80 it is 30·1 lakh tonnes while the consumption during this period is 25·8 lakh tonnes to 53·6 lakh tonnes. If we take any year between 1974-75 and 1979-80 every year we find that there is great gap between production and the consumption and it has become necessary for us to make imports of the fertilisers at very high prices. It would therefore, be necessary to consider the question of imports of fertilisers and the indigenous production of the fertilisers and we have to see in what way we can provide sufficient quantity at cheaper rates to the farmers.

As far as the imports are concerned I feel it is necessary at least for some years to come to import fertilisers because the experts have said that there are no known deposits of potash in India and therefore, the country has to depend upon the imports of the fertilisers. But as far as the imports are concerned there are certain constraints and I would request the hon. Minister to consider as to what steps he should take to remove these constraints. The first difficulty that is experienced is that there is inadequate availability of certain important fertilisers which are necessary for our country. The second difficulty I find is that there is trend of moderate to sharply rising prices in international markets which farmers are not in a position to paye; and, third, inability of certain suppliers to honour contractual commitments of delivery schedules. Last year many of the contractors abroad were not in a position to fulfil their commitments and, therefore, we could not get all the import quota. I am told and I have also seen from the Report of the last year that the Government was aware of these difficulties and, therefore, high-powered committees were appointed under the Chairmanship of Secretaries A & C. We do not know the recommendations made by these committees. We do not know whether the reports submitted by these committees were useful to the government in overcoming this particular difficulty.

Now, I would like to invite the attention of the hon. Minister to the indigenous production of fertilisers. Indigenous production of fertilisers has not kept pace with the growth of fertilisers consumption thus necessitating dependence upon the imports. With reference to this there are certain constraints and difficulties. I find from the various reports which have been circulated to us that the indigenous production becomes difficult because of three factors mainly, viz., inadequate availability of power; constraint in availability and movement of raw-material and equipment breakdown.

Now, Sir, there should be coordination between various Ministreies and Departments. I would, therefore, suggest that inter-departmental committees be constituted. I do not know whether such committees have been constituted because I could not come across reports of such committees. Sir, we find if one Ministry or Department is functioning the other connected one is not functioning with the result that we are not in a position to get proper results.

As regards chemical fertilisers I find that production of chemical fertilisers becomes difficult because of escalation of prices of raw-material and dwindling resources of energy supply. I would like to make an ardent appeal to the hon. Minister that it would be necessary to find other sources of this fertiliser.

While considering the question of alternatives I would like to invite the attention of the hon. Minister to various reports and recommendations made by the various committees and bodies.

Those recommendations have only remained on paper. They have not been implemented. Yesterday I came across a Report of the Ministry of Agriculture. That is regarding the use of micro nutrients for crop production. There was a Seminar held in Collaboration with the FAO of the United Nations and the Norwegian Government in Septemmer, 1979. They have made certain re-recommendations. Now, Sir, I do not know whether these recommendations have only remained on paper, because, I do not find any implementation in regard to them, nor any reference made to these, anywhere. So, I would like to know what is the follow-up action which has been taken in this regard and the result of it.

I would like to suggest that the future fertilizer strategy for enhancing soil fertility under the circumstances should be based on an appropriate bland of organic, bio-fertilizers and chemical fertilizers. Under the circumstances I would request the Government to consider whether it is possible to blend organic and bio-fertilizers and chemical fertilizers. There is a programme for the development of local manurial resources with various components like Machanised composing; Bio-gas development· Sewage and Sullage utilisation and Green-maruring. These programmes should be taken up for speedy implementation. These fertilizers should be given to the farmers in right time, at right price, and in right quantity. But our experience is otherwise. They supply fertilizer to farmers when they are not needed. Government must provide the farmers with latest farming techniques. The need of the hour is machanised agriculture. The yield of cereal per hectare in India is lower than the world average and the margin is widening. Though the area under maize has increased from 4.5 per cent to 5.2 per cent during 1961 to 1976, its share of the total world production has remained stagnant at 2 per cent only. In this way what happens is that only some new areas under cultivation can be brought about, but production will not increase. During the same period. the per capita consumption of Pulses declined by about 34 per cent. I may say that the position is not better as regards other food crops.

There is one other matter to which I would like to invite the attention of this honourable House. According to the Birla Institute of Scientific Research, extensive machinisation of agricultural operations is the only way by which we will be able to raise food production. An immediate reaction to this suggestion will be that machinisation increases unemployment significantly, but this is not true.

PROF. N.G. RANGA : May I interrupt? Machanisation is harmful for small farmers and it increases unemployment.

SHRI BAPUSAHEB PURULEKAR : I anticipated objection from Prof. Ranga when I thought of making this submission.

PROF. N. G. RANGA : You cannot persuade me. Millions of farmers cannot be persuaded.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Now I will refer to a report of the Government Institute at Hyderabad.

A study conducted by the International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics has revealed that though the participation of family members in farms that have begun using tractors has declined, that of hired hand has shot up. The second point to which I would like to draw the attention of this House is that the use of tractors has also gernerated non-farming employment as in other fields of mechanisation. I will give an instance. The district of Karnal in Punjab which has 4800 tractors and 40,000 pump sats, has 30,000 people engaged in servicing and maintenance operations. as well as making fuel and spares available to these tractors. This is according to the report of the Agriculture Ministry. Now, you may kindly consider whether the employment is more becuase of the mechanisation or whether it is less in this particular form of agriculture. I may submit that the tractors do not displace human beings, but they displace the bullocks. The reduction in the use of animals for agricultural operation is 70% in Punjab, 40% in Gujarat and 62% in Uttar Pradesh. This desirable de-

[Shri Bapusaheb Parulekar]

ployment, in my opinion, is not wrong becuase the fodder consumed by the bullocks can be diverted to feed the milch animals. I would like to draw the attention of the House to the report of the Agriculture Ministry. I find from the report that at the current rate of population increase, food production will have to the be stepped up to 240 million tonnes by the turn of the century and the experts say that the extra energy needed to attain this target is estimated at 35 million horse-power. It is possible to attain this only by mechanisation.

I have suggested in my amendment that attention should be paid to horticulture. My district, Ratnagiri, produces mangoes and cashews. It products the famous 'Alfanso' mangoes. I would request the Government that sufficient incentives should be given to boost up the production of mangoes for export purposes. Now, whatever little quantity we are exporting, the benefit does not go to the farmers but the middlemen are getting the profits. I request that this point should be considered and I support the Resolution. If this is done, there will be good production of mangoes and all the hon. Members will be in a position to get 'Alfanso' mangoes from my Constituency, that is Ratnagiri District.

SHRI A.T. PATIL (KOLABA) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by my hon. friend Prof. Satya Deo Sinha which concerns with steps to increase food production. He has suggested a number of measures which he desires that this House should recommend for implementation. In his Resolution, he refers to proper incentives to the farmers by (a) reducing the prices of fertilisers and other inputs (b) providing irrigation facilities (c) acquainting them with latest farming techinques (d) ensuring remunerative prices of thier produce and (e) introducing crop and cattle insurance schemes. So far as these suggestions are concerned I do not think that there will be any difference of opinion, with respect to them. I do not wish to deal with each and every aspect of it in detail.

Initially, I would invite the attention of this House and of the Government to one aspect of the problem and that is our approach to this issue. Let me submit very humbly that we are not business men to look to the profits and losses in a particular business activity. We are not even purely administrators who are supposed to be interested in the proper, effective and economic implementation of the policies which entail restrictions on the methods that may be used so as to effect economy, and to bring about better results. But, we are the policy makers, makers and moulders of the destiny of the millions of people in this country and, therefore, our attention should be directed to the destiny of the people, the common man, in this country and to make him an effective citizen of this country, who will be able to exercise the fundamental rights and other constitutional rights enshrined in our constitution, supposed to be exercised and enjoyed by him. That is the approach that we must have before searching for solutions to the problem.

Now, in order to achieve that particular objective, or to make the approach effective and to see that the economy of this country improves, we should be ready to change the existing policies if necessary and also to adopt new policies as well. If that approach is undertaken, then let us not look to the agricultural sector from the traditional point of view, namely that agricultural sector is just like any other sector, where you can think in terms of more production by giving the farmers merely remunerative prices in terms of money, or prices based on a particular method of calculation or assessment of the value of their labour. We have to change the concept of our assessment or the valuation of their labour. We have to change the traditional approach to see that this man who is the pillar of the entire economie and constitutional structure of this country gets better strength and better living.

What is the position of this man in the agricultural sector? The position is that the poverty line in the agricultural sector has not gone down in the sense that the percentage of population below poverty line has not been reduced. If you look to this population, you will find that the poverty line which was at a particular level ten or twenty years before has remained there without appreciable variation. One can get recent statistics in this respect from the Government , but I need not digress on this point in detail. The fact remains that the poverty line in respect of the agricultural population remains at a particular level. The economic condition of the agriculturists as a whole, has not improved.

The reason is very simple, and it is twofold. The first reason is that their labour has not been properly assessed and they have not been properly compensated in terns of their practical requirements in life for their labour. I am not asking or speaking in terms of raising prices, or lowering prices or comparing prices of the agricultural produce. I am, at the moment, concerned with giving to the labourer, may be in agriculture, or for that purpose any labourer, who is a citizen of India and who exerts his labour , proper compensation, and value of his labour in terms of his needs in life and living.

Secondly, if in the process we find that he cannot be compensated fully for his labour in agricultural sector, then we should shift him to some other sector where he will get better employment. Here is a sector, the agricultural sector, where there is a patent under-employment, and unemployment and also a disguised unemployment and under-employment. There is a lot of that and you will have to think of this aspect as well.

It could be said that there are so many subsidies and you can cite figures from the reports of the Governments and other documents that such and such subsidies have been given to them. You can also cite statistics about the capital expenditure in the agricultural sector and the irrigation sector and you can also cite the statistics with regard to modernisation of agriculture etc.

But, the two other aspects which have been referred to in this resolution are very material. One is introducing crop and cattle insurance schemes to save the farmer from the uncertainties and vagaries of nature, etc. and the other is ensuring remunerative price of the agricultural produce to the farmers. When I talk of remunerative price, I do not look to the prices in terms of money.

For instance, a particular holding extending over 5 or 6 or even 7 acres if so found appropriate, may be taken to be a normal holding capable of sustaining one family. If the holder of such a holding is to be a decent citizen of this country, he must get the remuneration for his labour—not on the basis of produce, but for the labour he puts in. He must get sufficient remuneration for maintaining himself and his small family if so, the method of assessing the prices of agricultural produce must be reviewed; and we should see...... (*Interruptions*) This should be done.

16.56 hrs

[SHRI CINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

Secondly as the hon Member Mr. Parulekar has rightly pointed out, mechanisation of agriculture is a must. It is essential (*Interruptions*) It is not Bombay economics. It is the economics of the country. I would rather say that it is a part of the economy of the world. The world is progressing in a particular direction; and if we forget that direction, we will be forgetting ourselves and the nation. So, mechanization is a must. How can it be brought about, is for you to think about. There are different ways. I would suggest some.

For this purpose, fragmentation must stop. The process of consolidation must be undertaken. The law of succession and inheritance must be changed. The law on transfer of agricultural land must also change. And, you must find out a way in which you can arrive at a size of the holding which will be viable and feasible for mechnization. For that purpose, you can have even collective or cooperative farming units. Unless that is done, I think agricultural economy in this country is not going to improve, in the sense that although you can increase production, you cannot increase the economic level of an agriculturist, i.e. of a person relying on agriculture in this country. The question of big and small agriculturists will not arise, if you assess primarily the labour that is put in. If we assess simply in terms of prevailing wages or prices in terms of money we will be going in a different direction. You should relate the labour to the level of his living. Then only you can understand and save this small man who puts in labour in agriculture.

With these words, I support this Resolution even though it talks of traditional methods.

*SHRI R. K. MHALGI (Thane): Mr. Chairman, Sir. I rise to extend my full support to the resolution moved by my hon. friend, Prof. Satyadeva Sinha. It reflects the burning problems which millions of our farmers face. Out of an estimated population of 75 to 80 crores, according to the current census operations, the farming community would be about 50 crores. That figure should give an idea of the magnitude of the problems that the resolution seeks to deal with.

The mover has made some suggestions for increasing the food production in our country but some other points need to be made. Much has to be done in the matter of reducing rates of power for agricultural purposes, cement, steel, pump sets, bullocks and other inputs. I shall, however, concentrate on the aspects of our agriculture which I sought to raise in the amendments of which I have given notice.

The farmers must be ensured of remunerative prices; if that is not done, there would be no encouragement to produce more. The Agricultural Prices Commission, was appointed as late as in 1965 and the agriculturist intersets continued to be neglected for

---

*The original speech was delivered in Marathe.

[Shri R. K. Mhalgi]

the first almost two decades of our independence. The A. P. C. has also failed to deliver the goods; the constitution of the Commission being what it is, the farmers have no hope of any benefit. The Commission should be dissolved and a new body appointed in which there should be representatives of farmers, consumers, merchants and other interests, including agricultural experts. Such a body can inspire confidence among the farmers in the matter of being able to get remunerative prices which alone will encourage them to produce more.

17 hrs.

The question is , how we are going to solve the problems of agriculture which face us today in the absence of the new commission suggested by me. My party has prepared a time schedule according to which action can be taken to come to grips with the problems. Certain criteria are vital in the matter of fixation of remunerative prices of agricultural produce—(i) the present living index must be taken into consideration; (ii) there must be some corelation between the industrial goods and agricultural goods prices; (iii) the cost of production must form an important basis on which the prices fixed should rest; (iv) the capital investment of land and the cost of other inputs must not be forgotten. (v) the members of a farmer's family must be considered as wage earners and their salaries included as an item in the cost of production.

The APC must announce the prices before a crop is sown and not after it as is the usual practice. The farmer must know what he would get when the harvest is in; only then can be make an intelligent choice. For Maharashtra the prices must be announced before the end of May, 1981.

I would suggest the following prices for the coming season: (i) for jawar and bajra Rs. 150/-per quintal; (ii) paddy 165 rupees per quintal; (iii) wheat Rs. 200/- per quintal; (iv) onions Rs. 100/-per quintal; (v) sugarcane Rs. 300/-per tonne; and (iv) cotton Rs. 700 per quintal.

Credit facilities is another factor to inspire the farmers to produce more. Unfortunately, the Government has always discriminated against the agricultural sector *vis-a-vis* the industries. In the year 1975-76 India's agricultural production was valued at Rs. 24,841 crores but the credit supplied was mere Rs. 3,148.9 crores, but industrial sector get Rs. 6,663.5 crores as against a production value of Rs. 9,555 crores. The percentages work out to: industry 70% of the total value of its production and agriculture a mere 12 1/2%. That shows how the farmers were neglected.

The institutional finance for agriculture should be increased from 30% to 60%. The small and marginal farmers must be encouraged to become members of co-operative societies so that they can get loans easily. The rate of interest should be 7½% on small term loans, and 6% on medium term loans. The law on the remission of agricultural loans under certain condition should be passed for the whole country. That would be the proper way to encourage the agricultural sector.

With these words, I support the resolution.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, प्रो० सत्य देव सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं ।

देश की उन्नति कृषि उत्पादन पर और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करती है परन्तु अपने देश में जहां पर 75 प्रतिशत किसान हैं, हम अभी तक भी, मैं देख रहा हूं, नेचर पर बहुत ज्यादा डिपेन्ड कर रहे हैं । अभी भी भगवान की जब हम पर कृपा हो जाती है और वर्षा अच्छी हो जाती है, तो किसानों की पैदावार बढ़ जाती है और जब प्रकृति की कृपा नहीं होती है, तब अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है । कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और कहीं सूखा पड़ जाता है और फिर हमारे यहां अनाज का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है और हमारे देश की स्थिति बहुत ही विषम हो जाती है । इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक हम सिंचाई के क्षेत्रों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको विकसित नहीं करते हैं, तब तक हम कृषि उत्पादन में स्थायित्व नहीं ला सकते । इस कृषि उत्पादन में स्थायित्व होने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा सिंचाई की योजनाओं पर, उनके विचार पर और उनके विकास पर । इसके लिए मैं विशेष तौर पर जोर देना चाहूंगा । हमारे कृषि मंत्री जी अब सिंचाई मंत्री जी भी हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का निर्माण कार्य

बहुत ही मंद गति से चल रहा है । और इस के ऊपर केन्द्रीय सरकार ध्यान देती, इस के ऊपर राजस्थान सरकार भी ध्यान देती—वह एक राष्ट्रीय नहर है—तो हमारा जो यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, यह क्षेत्र हिन्दुस्तान के दूसरे क्षेत्रों को भी अन्न दे देता और हमारा देश कभी का आत्मनिर्भर हो गया होता, परन्तु इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और अब स्थिति यह बन गई है कि जिस नहर का निर्माण कार्य 15 वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहिए, वह अभी तक सम्पन्न नहीं हुआ है और पता नहीं कि उस के सम्पन्न होने में कितना और समय लगेगा । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छटी पंचवर्षीय योजना में इस के बारे में जो आंकड़े और हैं वे बहुत ही आशाप्रद हैं और उन के मुताबिक छटी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर का पहला और दूसरा फेज, दोनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा । छटी पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार के लक्ष्य बनाए गये हैं अगर वे पूरे हो जाते हैं और निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र जेसलमेर, बीकानेर और गंगा नगर आदि का है, वह हिन्दुस्तान को बड़ी पैदावार देगा, बहुत सा अनाज पैदा कर के देगा और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा, वह काफी तरक्की करेगा । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो नहरें बनाने का काम है, जितनी भी नहरें हिन्दुस्तान के अन्दर बन रही हैं, उन का निर्माण-कार्य कहीं 4 साल पीछे है, कहीं 5 साल पीछे है और कहीं 10 साल पीछे चल रहा है । हमारे जो मंत्री मंडल के सदस्य हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी नहरें बन रहीं हैं, वे एक एक नहर के बारे में जांच करें और उन को पूरा कराने की कोशिश करें । इस छटी पंचवर्षीय योजना में जो भी दूसरे कांस्ट्रेट्स हैं, आब्सट्रंक्शन्स हैं, उन सब को हटाने का प्रयास करना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहरों के पानी के बटवारे के बारे में बहुत से डिस्प्यूट्स भी हैं और उन में कुछ ट्रिब्यूनतस् के पास हैं और कुछ चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस के सामने भी आए हैं । मैं यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट उन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी निपटाए । उन का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए । अभी हमारे जो माही और कछाना के प्रश्न हैं, और नर्मदा के प्रश्न हैं अगर ये हल हो जाते हैं तो हमारे बाड़मेर और जाल्लौर—जेसलमेर मैंने गल्ती से कह दिया था—के बहुत से क्षेत्र सिंचित हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में पहले भी एग्रीमेंट हुआ था । यह एग्रीमेंट गवर्नमेंटों के बीच में हुआ था । उस एग्रीमेंट के अनुसार हम ने बड़ा भारी डेम बनाया और बीसियों अन्य प्रयास किये लेकिन अब उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है । यह एग्रीमेंट 1966 में गुजरात के मिनिस्टर और राजस्थान गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने किया था । अगर इस एग्रीमेंट पर अमल होता रहता तो हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सकता । इसलिए मैं विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि नहरों के निर्माण के बारे में आपको गति देने की कोशिश करनी चाहिए ।

दूसरी बात इस देश में लघु काश्तकार, स्माल और मारजिनल काश्तकार की संख्या बहुत ज्यादा है । अभी जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बड़े-बड़े काश्तकारों ने फायदा उठाया है, मध्यम श्रेणी के काश्तकारों ने फायदा उठाया है । जिनके पास ट्रेक्टर हैं आज उनकी

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

पोजीशन अच्छी है । यह मैं मानता हूं कि आज के युग में उनकी उन्नति होनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए । परन्तु हमें यह भी देखना है कि हमारे जो स्माल और मारजिनल फार्मर्स हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, उनके लिए यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे डेवलपमेंट्स प्रोग्राम हैं, उनको सबसीडी वगैरह देने का भी प्रोवीजन हमने किया है, और भी उनके लिए बहुत सी व्यवस्थाऐं हम कर रहे हैं परन्तु इन कार्यो को और गति देने की आवश्यकता है । क्योंकि आज यह स्थिति पैदा हो गयी है कि स्माल और मारजिनल फार्मर्स बड़े बड़े काश्तकारों के कम्पीटीशन में स्टेण्ड नहीं कर पाते हैं । यह स्थिति पैदा हो गयी है कि वे अपने छोटे छोटे खेत जो कि इकोनोमिकल नहीं हैं उनको छोड़ कर वे शहरों की ओर बढ़ रहे हैं । उनके पास छोटे छोटे खेत हैं जिनकी उपज पर उनके दस दस पन्द्रह-पन्द्रह लोगों के परिवारों का गुजर-बसर नहीं हो सकता है । वे छोटी छोटी होल्डिंग्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं । इस लिए उनकी स्थिति बहुत खराब है।

स्माल और मारजिनल फार्मर्स को क्रेडिट फेसिलिटीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब अकाल पड़ता है तो लोन वगैरह की रिकवरी सस्पेंड कर दी जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि जब तीन साल तक लगातार अकाल पड़ता हो तो लोन वगैरह की वसूली केवल सस्पेंड ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि माफ कर दी जानी चाहिए । आज हमारे क्षेत्रों में तीन सालों से लगातार अकाल है । आप अगर उनसे सब की सब रेवेन्यु की रिकवरी करना चाहें या लोन की रिकवरी करना चाहें तो वह देने की स्थिति में नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी होनी चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव्ज दिये जाने चाहिए कि उन एरियाज के लोगों से जहां तीन साल अकाल पड़ा है रेवेन्यु और लोन की रिकवरी केवल सस्पेंड ही नहीं होनी चाहिए बल्कि माफ कर दी जानी चाहिए ।

भूमिहीन किसानों का प्रश्न सब से महत्वपूर्ण है । वे मजदूरी करते हैं और दूसरों पर डिपेंड करते हैं । अभी तक हम उनको मिनिमम वेजिज दिलाने की गारन्टी नहीं कर सके हैं । वास्तविक रूप में जब तक हम यह गारन्टी नहीं कर सकेंगे तब तक हम उनका भला नहीं कर सकेंगे । बहुत से प्रांतो में मिनिमम वेजिज के बारे में निर्णय लिये गये हैं लेकिन उनके बारे में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकार इनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में राज्य सरकारों को कहे । मैं तो चाहता हूं कि मिनिमम वेजिज के बारे में सारे देश में एक-सी पालिसी हो । तभी हम इसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे और इन गरीब काश्तकारों को कुछ रिलीफ दे सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने कृषि की दृष्टि से उन्नति की है और विकास किया है । इसमें जो हम आगे बढ़े हैं उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की बजह से आज हम आत्म-निर्भर हो सके हैं जबकि समाजवादी देश इसमें आत्म-निर्भर नहीं हो सके हैं। हम आत्म-निर्भर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आधुनिक युग में हम उन्नति करें । इस कार्य में हमारी केन्द्र सरकार ने भी मदद की है, सहयोग किया है । इसके लिए हम केन्द्र सरकार की प्रशंसा करते हैं, परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में और ज्यादा कार्य करे और ज्यादा कार्य

करके किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करे, क्योंकि किसानों को हमें उन्नति के पथ पर लाना है ।

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Sir, I rise to support the Resolution moved by Shri Satya Deo Sinha, regarding some steps or measures to be taken for increasing food production.

Sir, as you are aware, our country is an agricultural country, our economy is mainly dependent on agriculture even though we have got some industries. Whenever there is a loss of agricultural production due to drought or floods or such other national calamities, our economy is affected. But whenever the agricultural production is high, the Government, I mean whichever may be the Government, usually says that due to their efforts the production has increased. But according to the statistics, when the climate is good and the conditions are favourable, then only agricultural production is increased. It is stated in the *Economic Survey:*

> "In 1980-81 weather conditions have been normal in most parts of the country. As a result, agricultural production this year may increase by about 19 per cent over that of 1979-80."

But nothing is told about the Government policies or the Government measures. However, there is a tendency of fluctuation in the agricultural production. As a consequence, we are to take necessary measures so as to increase the production. I am giving you some instances. Here, I have collected from the *Economic Survey* figures to show fluctuation in the production of foodgrains. In the year 1973-74, the production was 1,04,664.5 thousand tonnes whereas in 1974-75 it was 99826.2 thousand tonnes. The decrease in the year 1974-75 in relation to 1973-74 was 4838.3 thousand tonnes. In the year 1975-76 the production was 121034.3 thousand tonnes. In the year 1976-77 it was 111166.8 thousand tonnes. The deficit is 9867.5 thousand tonnes.

From these figures it is clear that the fall in production has been increased by more than 100 per cent. Again in the year 1978-79 there was less production in relation to previous five years. In this way the production is fluctuating.

Now I want to point out the yield per hectare of foodgrains in this country. Our production has not ncreased. In the year 1975-76 it was 944 kg. per hectare. In the year 1976-77 it was 894 kg. per hectare. That means the production decreased by 50 kg. per hectare. In the year 1977-78 there was yield of 991 kg. per hectare. In the year 1978-79 it was 1022. Due to natural calamities in the year 1979-80 it was 878 kg. per hectare. I do not like to say that at this time the production is less and during the Janata regime the productivity per hectare was more. I do not like to say that it was because of their good efforts. So, also what I want to mention is that only due to favourable climatic conditions we were producing more.

MR. CHAIRMAN: Please keep the time in mind.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Until and unless we give the opportunity and we take the agricultural labour into confidence, the production will not be more.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (RAO BIRENDRA SINGH) : That is his point.

SHRI MUKUNDA MANDAL: We have land reforms. We have abolished Zamindari system. But the surplus land has not been distributed among the landless people. This factor is very important. Here, Government is very much interested to produce more. Different measures have been taken by them. I want to suggest that until and unless you adopt the land reforms in the real sense of the term, it is not possible to produce more food.

I urge upon the Government that the concentration of land that has taken place during the years should not be allowed to continue. The surplus land should be taken from the land hoarders and distributed among the poor people and poor peasantry.

Agricultural labourers have lost their land due to the wrong economic policy of the Government. Due to wrong policy of the Government, they have lost their land whatever they owned earlier. The result is that the number of agricultural workers is increasing.

All sorts of money lending by the private money-lenders should be prohibited.

In rural areas the agricultural workers are not paid their minimum wages. They are denied their wages. They work hard. They produce food. They give

[Shri Mukunda Mandal]

us food. They give food stuffs to the nation. But they are denied the minimum wage. So, I want to urge upon the Government to take necessary steps for giving the minimum wage.

I want to further mention that they do not get work for all the 12 months in a year. They get work only for 3 months. For 9 months, they are unemployed. Consequently, they have to go to a village money-lender. Either you give them the work or you give them an unemployment allowance to the agricultural labourers. Only in that case the production will be more. The lending from private money-lenders would be stopped only when the Government comes forward to give loans from the Government treasury or nationalised banks to the poor and marginal farmers.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member's time is up.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Lastly, I want to mention about irrigation. The total area under foodgrains is 126 million hectares. In the year 1974-75, 32·31 million hectares were under irrigation and in 1977-78, only 35 million hectares were under irrigation. The progress is very slow. My contention is that we are not bringing a large area of land under irrigation. More and more area of land should be brought under irrigation. Then also the production of foodgrains can increase.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, खेती के उपकरण, खाद और बीज सस्ते दिलाने के साथ साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ बिजली और पानी भी ठीक प्रकार से उपलब्ध कराया जाय तब जाकर के ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकेगा ।

राजस्थान के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां 1 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली मिलनी चाहिये तब जाकर के वहां खेती और इंडस्ट्री का काम पूरा हो सकता है । मगर आज हमको करीब 80 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है इसलिये ऐग्रीकल्चर में भी 50 परसेंट से ज्यादा कट ऐग्रीकल्चर पर लगा रखा है जिससे प्रोडक्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है । कमी क्या है ? थीयन बांध पर जो बिजली प्रोजेक्ट बना है उसमें राजस्थान का भी हिस्सा था जैसा कि शुरू में ऐग्रीमेंट के समय तय हुआ था । मगर अब पंजाब और हरियाणा सरकारें हमको बिजली से वंचित करना चाहती हैं । इसलिये मेरा कहना है इस योजना से जो बिजली का हिस्सा हमको मिलना चाहिये था वह मिलना चाहिये तभी हमारा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ठीक प्रकार से हो सकेगा । इसी प्रकार से भाखड़ा और चम्बल योजनाओं से जो हमको बिजली मिलती है उसमें भी पंजाब सरकार हमको भाखड़ा से ठीक प्रकार से बिजली नहीं देती है और इसी तरह से चम्बल योजना से मध्य प्रदेश द्वारा हमको ठीक प्रकार से बिजली नहीं मिलती है । कहने का मतलब यह है कि हमें जितनी बिजली मिलनी चाहिये उतनी बिजली नहीं मिल रही है जिससे ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आ रही है ।

हमारे यहां दो ऐटमिक पावर प्लान्ट्स हैं मगर वह 5 दिन चलते हैं और 25 दिन बन्द रहते हैं । इस प्रकार बिजली के अभाव में राजस्थान का ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत सफर कर रहा है । इस बारे में समुचित व्यवस्था करनी चाहिये और नेशनल ग्रिड बना कर के राजस्थान को जितनी बिजली मिलनी चाहिये उतनी मिले तब जाकर के वहां ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकेगा ।

दूसरी बात मुझे राजस्थान कैनाल के बारे में कहनी है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय । हमने तो पहले सुझाव दिया था कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाय मगर केन्द्रीय सरकार इस सुझाव को स्वीकार नहीं करती है और उसकी वजह से कितने ही वर्ष हो गये । आज से कई वर्ष पहले यह पूरा हो जाना चाहिये था, मगर अभी तक पहला फेज ही पूरा हुआ है, दूसरा शुरू भी नहीं हुआ है । इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये ।

इसके साथ-साथ जो हमको राजस्थान कैनाल में 15 हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिये उसके बजाय 9 हजार क्यूसेक पानी मिल रहा है । इसमें भी पंजाब और हरियाणा की सरकारें बराबर दखल करती हैं और जितना पानी हमको मिलना चाहिये जिसकी वजह से हमारी ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सकती, उसमें भी बराबर कमी आती जा रही है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान देकर जितना पानी का हमारा शेयर होता है वह हमें दिलाया जाये जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके ।

इसी प्रकार नर्बदा में हमारा हिस्सा था । 5 लाख फिट पानी हमको मिलना चाहिये था, जब एग्रीमेंट हुआ । उस एग्रीमेंट को खत्म कर के अब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें, तीनों इस नर्बदा के पानी का अलग तरीके से बंटवारा कर के ले रही हैं और राजस्थान को जो 5 लाख क्यूसेक पानी उपलब्ध होना चाहिये था, वह न मिलने की वजह से बाड़मेर और जालोर को सिंचित करके इस डैजर्ट एरिया में हम प्रोडक्शन करना चाहते थे वह प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं । इसलिये हमको इसके जरिये जो हिस्सा मिलना चाहिये था, वह हमको मिलना चाहिये । अगर वह हमको मिले तो निश्चित तरीके से हम राजस्थान में इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं कि उससे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े भाग को हम खिला सकते हैं और हमारी जो कमी है, उसको भी पूरा कर सकते हैं ।

इसी तरीके से भीलवाड़ा जिले में 4 बांध हैं—मेजा, खारी, सरेरी और अरवड़ । यह चारों बांध मीडियम प्रोजेक्ट हैं । इन मीडियम प्रोजेक्ट्स को अगर माडर्नाइज कर दिया जाये, इनकी नहरों को पक्का कर दिया जाये तो निश्चित तरीके से जितनी जमीन आज सिंचित होती है, उससे दुगुनी सिंचित हो जायेगी । इसलिये माडर्नाइज स्कीम को भीलवाड़ा के इन चारों बांधों पर जल्द से जल्द लागू किया जाये ताकि ज्यादा क्षेत्र सिंचित हो सके और ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम कर सकें ।

इसके अलावा क्राप-इन्श्योरेंस नितान्त आवश्यक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हर साल अकाल पड़ता है और किसानों की खड़ी की खड़ी फसलें पानी के अभाव में जल जाती हैं जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है । इसलिये अगर क्राप इन्श्योरेंस होती है तो इससे किसानों को यह भरोसा हो जाता है कि अगर हमारी फसल नष्ट हो जायेगी तो भी निश्चित तरीके से हमें मुआवजा मिलेगा और हमारी गुजर-बसर के लिये सरकार व्यवस्था करेगी । इसलिये यह नितान्त आवश्यक है । हमारी सरकार की नीति भी है कि क्राप इन्श्योरेंस जल्द लागू किया जाये, इसलिये इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू किया जाये ।

राजस्थान एक बहुत बड़ा डैजर्ट एरिया है और उसमें एनीमल हसबैंडरी का काम भी बहुत होता है । इसलिये जानवरों का भी अगर इन्श्योरेंस किया जाये, गाय-भैंसों का इंश्योरेंस किया जाये तो निश्चित रूप से वहां के काश्तकारों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा ।

एक प्वाइंट मेरा लैंड रिफार्म के बारे में है । आपने सीलिंग का कानून लागू किया, मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों पर यह सीलिंग का कानून लागू किया गया । मेरा कहना है कि सीलिंग के कानून को और देखा जाये, क्योंकि इससे बहुत लोग बच गये हैं । बड़े-बड़े जमींदार अलग-अलग गलत नामों से जमीनों का बंटवारा करके सीलिंग से बचकर बड़ी-बड़ी होल्डिंग्ज पर आज भी काबिज हैं । इस प्रकार की व्यवस्था को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिये और यह जानकारी भी करनी चाहिये कि कौन-कौन लोग आज भी बड़ी-बड़ी जमींदारियों पर कब्जा किये हुए हैं । इसलिये इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से देखा जाना चाहिये तब हम इन जमीनों को लेकर इससे गरीबों को लाभ दे सकेंगे ।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

सीलिंग के तहत जो जमीनें आईं, जिन्हें काश्तकारों को बांटा गया था, जनता पार्टी का शासन जब आया तो जागीरदारों ने उन जमीनों को, जिनको कांग्रेस की सरकार के समय में छोटे-छोटे काश्तकारों, शिड्यूल्ड-कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को बांटा गया था, उन्होंने उस जमीन पर लाठी के जोर से कब्जा कर लिया । मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिये और जिन गरीबों की जमीनें जागीरदारों ने छीन ली हैं, उनको वापिस दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

बांडेड लेबर के बारे में बड़े-बड़े काश्तकार यह कहते हैं कि हमने बांडेड लेबर समाप्त कर दी है, लेकिन आज भी बड़े-बड़े काश्तकारों के यहां बांडेड लेबर मौजूद हैं, उनकी सिर्फ शक्ल बदल दी गई है । दूसरे तरीके से उन्हें अवैध पैसा देकर, 2, 2 और 3, 3 साल तक का पैसा देकर उनको जोर-जबर्दस्ती से अपने खेतों में रखा जाता है । वे लोग खुद खेती करते नहीं हैं और उनके जरिये से एक तरह से उन्हें बांडेड लेबर बनाकर जबर्दस्ती उनसे खेती कराई जाती है । इस प्रकार की व्यवस्था आज भी राजस्थान में जो बड़े-बड़े इलाके हैं, गंगानगर, कोटा बूंदी जहां बड़े-बड़े प्रोजैक्ट हैं, चम्बल में राजस्थान कैनाल, भाखड़ा का डंग कैनाल इस तरह के प्रोजैक्ट में उन लोगों को बांडेड लेबर की तरह रखा हुआ है । आज भी राजा-महाराजाओं की हजारों बीघा जमीन मौजूद है और इन जमीनों पर वह लोग इस प्रकार की बांडेड लेबर रखकर आज भी उनसे अपनी खेती-बाड़ी करा रहे हैं । इसके सम्बन्ध में भी हमारी सरकार को निश्चित तरीके से देखना चाहिये ।

जहां तक किसानों से ख़रीदारी करने का सम्बन्ध है, फूड कार्पोरेशन और काटन कार्पोरेशन के द्वारा जिस प्रकार से ख़रीद होती है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं । काश्तकारों से बिचौलिए गेहूं, कपास और दूसरी जिंसें ख़रीदते हैं और बहुत कम पैसा अदा करते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि कार्पोरेशन्ज़ किसानों से डायरेक्ट ख़रीद करें, ताकि वे लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें ।

आज राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल है और बहुत बड़ी पापुलेशन अकाल से पीड़ित है । भारत सरकार ने अकाल-राहत के लिए राजस्थान को बहुत थोड़ा सा पैसा दिया है, मगर राजस्थान की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं है कि वह इस भयंकर अकाल का सामना कर सके । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे कर अकाल-राहत के काम को ज्यादा बड़े पैमाने पर चलाया जाये, ताकि जो काश्तकार अकाल से पीड़ित हैं और खेती नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रोज़ी-रोटी की व्यवस्था की जा सके और वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

अजमेर और उदयपुर में डी पी ए पी लागू है । इन दोनों के बीच में भीलवाड़ा ज़िला है, जहां हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है । उसकी पांच तहसीलें —आसीन, मांडल, रायपुर, बनेड़ा और हुरड़ी—अकाल की चपेट में आ जाती हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर डी पी ए पी लागू किया जाये, ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

हमारे देश में 85 से 90 प्रतिशत किसान रहते हैं और उनकी तरक्की पर ही हमारे देश

की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना निर्भर करता है। इस प्रस्ताव के जरिये प्रो० सत्यदेव सिंह ने कई सवाल उठाने की कोशिश की है—खाद, बीज और कृषि-उपकरणों के मूल्यों में कमी की जाये, सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाये, किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जायें, फसल और पशुओं का बीमा किया जाये। ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ बातें माननीय सदस्य ने छोड़ दी हैं, जिनमें से एक की तरफ सभापति महोदय, आपने और कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, और वह है भूमि-सुधार का सवाल। जब तक बुनियादी भूमि-सुधार लागू नहीं किया जायेगा, तब तक उत्पादन में समय समय पर जो ब्रेक लगती रहती है, वह लगती रहेगी। इसलिए भूमि-सुधार आवश्यक है। जो कानून बने हुए हैं, उनको अमल में लाना चाहिए और आपने ठीक ही कहा है कि उन कानूनों को जमींदारों की चोट से बचाने के लिए इस विषय को संविधान की नवीं सूची में दाखिल कर देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो उत्पादन में रुकावट बनी रहेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने खेत-मजदूरों के सम्बन्ध में चर्चा की है। कृषि-मजदूर हमारी कृषि-व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, मगर उनकी चर्चा इस प्रस्ताव में नहीं है। पता नहीं, प्रोफेसर साहब ने इस चर्चा को क्यों छोड़ दिया।

प्रो० सत्य देव सिंह : मैंने अपने भाषण में उसके बारे में कहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : वह इस प्रस्ताव का अंग होना चाहिए था, क्योंकि किसान और मजदूर हमारी कृषि-व्यवस्था की धुरी हैं। गाड़ी के दो पहिये होते हैं। अगर वह नहीं चलेंगे, उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है, कृषि की उपज बढ़ाने में कठिनाई होगी क्योंकि सबसे ज्यादा हाड़-तोड़ परिश्रम खेत मजदूर करते हैं। लेकिन उनकी स्थिति सब से दयनीय है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो आपके रेजोल्यूशन का भी अंग नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो इस रेजोल्यूशन पर बोल रहा हूं।

तो उनका सहयोग लेना, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना यह सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। यह हो नहीं रहा है। मैं बता दूं, आप की सरकारें तो ज्यादातर राज्यों में हैं, क्या मजदूरी आप दे रहे हैं। अपने सूबे बिहार की बात बताता हूं, पांच रुपये की मजदूरी खेत मजदूर को आपकी सरकार नहीं देती है। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल में 8 रुपये 10 पैसे दिए जाते हैं, केरल में 8 रुपये मिल रहे हैं। जगह-जगह लोगों को 12 से 15 रुपये तक मजदूरी मिल रही है। तो इन दोनों का फर्क देख लीजिए।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल में 9 और 10 रुपये हो गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : 8 रुपये से तो कम नहीं है। लेकिन बिहार में तो पांच रुपये भी नहीं देते। राजस्थान में सुनते हैं उससे भी कम 2-3 रुपये देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम बढ़ाइए। इसी सदन में सवाल उठाया गया था कि पूरे हिन्दुस्तान के खेत मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनना चाहिए। उन्होंने भी रेफर किया और मैं भी चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी इस सदन के अन्दर कानून आप लाएं जिससे जो कृषि के अभिन्न अंग हैं खेत मजदूर उनकी स्थिति में सुधार हो सके। ऐसा कानून बहुत आवश्यक है। उन पर सामाजिक जुल्म जो होते हैं वह तो जग जाहिर हैं। हमारे सूबे में तो ये लोग दिन दहाड़े कत्ल

[श्री रामावतार शास्त्री]

कर दिए जाते हैं। जगह-जगह दूसरे सूबों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं।

दूसरी बात मैं लाभकारी मूल्य के बारे में कहना चाहता हूं। आज की स्थिति क्या है ? किसान जो सामान खरीदते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कोयला वह इस्तेमाल में लाते हैं, उसकी कीमत 328.8 प्रतिशत बढ़ गई है। किसान डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। उसकी कीमत 280 प्रतिशत बढ़ गई है। स्टील भी वह अपना मकान बनाने में में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत 265 प्रतिशत बढ़ गई है। बिजली जो उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है उसकी दर 232 प्रतिशत बढ़ गई है। उसी तरह सीमेंट और दूसरे जो मकान बनाने के सामान हैं उनकी कीमत 231.8 प्रतिशत बढ़ गई है। यह तो जो सामान वह खरीदते हैं उसकी हालत है। इसीलिए हम लोग बार बार मांग करते हैं कि औद्योगिक सामानों में और कृषि के सामानों के मूल्यों में पैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए ताकि किसान को लूटने वाले ये जो बिचौलिये हैं, इजारेदार हैं, टाटा बिरला या उनके छुटभैये जो मुनाफाखोर लोग हैं उनकी लूट से किसान को बचाया जा सके। लेकिन इन बिचौलियों से तो आपकी दोस्ती है, आप उनको हटाना नहीं चाहते। अगर दोस्ती नहीं है तो ऐलान कीजिए कि सरकार सीधे किसानों से सामान खरीदेगी और उनको लाभकारी मूल्य देगी। अगर ये बिचौलिये हट जाते हैं तो सरकार उन को लाभकारी मूल्य दे सकती है। आज जो समर्थन मूल्य आप तय करते हैं वह भी किसानों को नहीं मिल पाता। बिहार की सरकार ने 105 रुपये क्विंटल धान की कीमत तय की लेकिन धान बिका कितने में—90 रुपये में, 100 रुपये में।

राव बीरेन्द्र सिंह : गलत बात है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं चलेंज की बात तो नहीं करता लेकिन आप चलिए, इन्क्वायरी कर लीजिए और न हो तो एक पार्लियामेंट की एन्क्वायरी कमेटी बना दीजिए, सारा मामला तय हो जायगा। गेहूं पिछले साल आपने क्या तै किया था—105 रु०..

राव बीरेन्द्र सिंह: 117 रुपये।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, वह 117 रुपये हर जगह नहीं मिला। लेकिन आज हमारे बिहार में गेहूं बिक रहा है 200 रुपये से ऊपर। सो ये बिचौलिये कौन हैं ? यह फायदा कहां जा रहा है ? यह पैसे किसान के पास नहीं जा रहे हैं। तो आप देखें, औद्योगिक सामानों के मुकाबले में किसानों की चीजों की कीमत 30 प्रतिशत कम हो गई है। उनकी कीमत तो कम हो गई और उद्योगों में बनी हुई चीजों की कीमत बढ़ गई। इस तरह से दो तरफ से लूट होती है। किसान जब बेचता है, तब आप कम देते हैं और जब वह आपका सामान खरीदता है, जब कृषि के उपकरण खरीदता है, चीनी खरीदता है, खाद खरीदता है, तब उसको ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पैरिटी कीजिए।

किसान की उपज के मूल्य कौन तय करता है ? कृषि मूल्य आयोग तय करता है। उसमें कौन लोग हैं ? वे क्या सचमुच में किसानों के प्रतिनिधि हैं? आयोग ने ईख की क्या कीमत तय की थी ? 12.50 रु० क्विंटल तय की थी। लेकिन जब किसानों ने लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया, शान्तिमय तरीके से, जिसके लिए आपने उनको सजा दी, 50 से ज्यादा किसान कई सूबों में शहीद हुए आप से लड़ते हुए, तभी जाकर आपने बिहार में 22 रु० और यू० पी० में 23 रु० क्विंटल गन्ने का दाम तय किया।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिहार में कितने शहीद हुए ?

श्री रामावतार शास्त्री : वे होने को हैं, आप आइए। लकिन आपको हिम्मत नहीं हो रही है। जो किसानों के ऊपर बकाया है, चाहे वह मालगुजारी का हो, कर्जे का हो, टैक्स का हो, उनको देने की स्थिति में आज वे किसान नहीं हैं। इसीलिए उनके आन्दोलन से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में जो आन्दोलन हुए, उनसे विवश होकर आपने 200 करोड़ रु० की छूट दी है। अपने मन से तो आप किसानों को नहीं देना चाहते हैं। बिहार में भी आपकी सरकार को एलान करना पड़ा कि इन-इन बातों में छूट दी जाएगी। अभी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वे जाकर वसूली कर सकें। ...... (**व्यवधान**) ......मैं यह कहना चाहता था कि जो कृषि मूल्य आयोग हैं, उसको पहले आप परिवर्तित कर दीजिए, उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को रखिए, ताकि सही मायनों में जो किसान खर्च करते हैं, उसके अनुरूप वाजिब मूल्य तय किए जा सकें। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अगर लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, तो जाहिर है कि वे आन्दोलन करते रहेंगे। इसलिए मैं आपको निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं——पहला यह कि नकदी फसलों और खाद्यान्नों समेत सभी कृषि उत्पादों के लाभप्रद मूल्य कटाई के मौसम से काफी पहले निश्चित लिए जायें; दूसरा——मूल उत्पादकों को कटाई के मौसम के आरम्भ से ही लाभप्रद मूल्यों की अदायगी की गारंटी दी जाए, जिससे कि उन्हें मजबूरन बिक्री के लिए बाध्य न होना पड़े; तीसरा——मूल उत्पादक को दिए जाने वाले और वास्तविक उपभोक्ता से लिए जाने वाले वास्तविक मूल्य में देश भर में पूरे वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक का अंतर न हो; चौथा——कृषि आदानों और आवश्यक औद्योगिक सामान समुचित रूप से कम मूल्यों पर मुहैया कराये जायें तथा कृषि उत्पादों और औद्योगिक समान के मूल्यों में साम्य सुनिश्चित किया जाये।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन चार बातों को जरूर मानें। अगर मानेंगे तो किसानों को आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वरना वे आन्दोलन चलते रहेंगे और आप गोली चलाते रहेंगे। इसलिए आप उन किसानों को ऐसा मौका मत दीजिए। आप कम से कम उनको लाभकारी मूल्य अवश्य दीजिए, तभी वे चुपचाप रहेंगे।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, February 28, 1981/Phalguna 9, 1902 (Saka).

GMGIPMRND—3963 L.S.—22-4-81—890